

उनाकोटी में हैं भगवान की 99,99,999 मूर्तियां! किसने और कब बनवाई ये प्रतिमाएं

Travelling

भारत के ऐसे कई मंदिर हैं, जिनका रहस्य लोगों को हैरान कर देता है। ऐसा ही रहस्य है उनाकोटी में बनीं 1 करोड़ से एक कम भगवान की मूर्तियों का। चलिए आपको उनाकोटी के बारे में सबकुछ बताते हैं।

• जालंधर ब्रीज . फीचर

भारत में हर राज्य, शहर, गांवों में आपको अनोखी चीजें देखने और सुनने को मिलेंगी, खासतौर पर धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई। कहीं पर किसी मंदिर में भगवान के अनोखे दर्शन की कहानी मिलेगी, तो कोई मंदिर पानी में डूबा हुआ दिखेगा। आज हम आपको जिस मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं, वह सीधा भगवान शिव से जोड़ी जाती है और वहां पर 1 करोड़ से एक कम भगवानों की मूर्तियों बनी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर लगता है जैसे किसी शिल्पकार ने इन्हें शिद्दत से तराशा है और यहां पर भगवान शिव, गणेश, राम, लक्ष्मी, दुर्गा समेत कई भगवानों की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। सवाल

यह उठता है कि आखिर चट्टानों पर इतनी प्रतिमाएं किसने और कब बनवाईं। चलिए आपको इन मूर्तियों के रहस्य के बारे में बताते हैं।

उनाकोटी में हैं 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां : पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में रघुनंदन पहाड़ियों की गोद में बसा 'उनाकोटी' एक प्राचीन स्थल है। उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से एक कम। इन चट्टानों पर 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां बनी हुई हैं और इसी वजह से इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ गया। इस स्थान पर चट्टानों को काटकर लगभग इतनी ही संख्या में मूर्तियां और आकृतियां उकेरी गई हैं, जो देखने में बेहद आकर्षित लगती हैं।

किसने और कब बनवाई ये प्रतिमाएं : यहां पर सभी भगवानों की मूर्तियों के साथ रावण की प्रतिमा भी बनी हुई है, जिनके

हाथ में धनुष है। सबसे बड़ी मूर्ती यहां पर भगवान शिव की है और उनके आस-पास नंदी बने हुए हैं। इन मूर्तियों को कब और किसने बनवाया आजतक इसका रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है। इन मूर्तियों को लेकर कई कहानियां वहां प्रचलित है और सभी में भगवान शिव मुख्य हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पाल साम्राज्य के दौरान यह जगह बनी, तो कोई कहता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में यह जगह बनी। अभी तक इन दावों को लेकर कुछ भी पुख्ता नहीं है।

भगवान शिव ने दिया सभी को श्राप : डिस्कवरी प्लस के शो एकोत में बताई गई पहली कहानी ये है कि सभी भगवान इसी रास्ते से होकर काशी जा रहे थे। रात में थकान के कारण सभी ने रघुनंदन की पहाड़ियों पर आराम करने का सोचा। भगवान शिव ने सभी को कहा कि सूर्य निकलने से पहले ही उठकर चलना है। दुर्भाग्य से अगली सुबह किसी भी देवी-देवता की नींद नहीं खुली और भगवान शिव ने उन्हें मूर्ती बनने का श्राप दिया और खुद वहां से चले गए। सवाल ये है कि शिव जी भी चले गए थे तो उनकी मूर्ती क्यों क्यों बनी है।

कल्लू कुम्हार ने बनाई मूर्तियां : अन्य किंवदंती है कि कल्लू कुम्हार ने माता पार्वती और शिव जी को इस रास्ते से



कैलाश की ओर जाते देखा, तो उन्होंने भी कैलाश पर्वत साथ लेकर चलने को कहा। ऐसे में मां पार्वती ने कुम्हार की परीक्षा लेने के लिए 1 करोड़ देवी-देवता की मूर्तियां बनाने को कहा और कल्लू ने रातभर मेहनत कर मूर्तियां बनाई लेकिन इसमें एक कम रह गई। इस वजह से वह



कैलाश नहीं जा पाया और इस जगह को उनाकोटी कहा जाने लगा।

विश्व धरोहर स्थल बना : अब उनाकोटी सिर्फ धार्मिक तीर्थ ही नहीं बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने उनाकोटी को राष्ट्रीय धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया है। इसे लॉस्ट हिल ऑफ फेसेज भी कहा

जाता है, इसका मतलब हुआ चेहरों का खोया हुआ पहाड़। यहां पर लोग दूर-दूर से घूमने और इन मूर्तियों को देखने आते हैं। यहां पर लोगों को अजीब सी शांति का एहसास होता है। यहां पर आस-पास हरियाली फैली हुई है, जहां का नजारा आंखों को सुकून देता है।

FITNESS MANTRA

सेब या अमरूद! कौन सा फल खाने से मिलेगा ज्यादा पोषण, रिजल्ट जान चौंक जाएंगे

हर रोज सेब खाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हेल्दी रहने और सही न्यूट्रिशन की पूर्ति के साथ वेट लॉस में सेब खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है तो जरा रुकें, बारिश में मिल रहे अमरूद की न्यूट्रिशन वैल्यू जरूर जान लें, चौंक जाएंगे...



• जालंधर ब्रीज . फीचर

'ऐन एप्पल एं डे,कीप्स डॉक्टर अवे' ये इंग्लिश वाली कहावत तो खूब सुनी होगी। हेल्दी रहना है या फिर वेट लॉस करना हो सबको सेब की याद आती है। डाइट में हर दिन सेब खाते भी खूब होंगे। लेकिन 150 से 250 रुपये तक कीमत में मिलने वाले ये सेब हर किसी के बजट में फिट नहीं होते। लेकिन टेंशन ना लें, सस्ते से मिलने वाले अमरूद के न्यूट्रिशन सुनकर आपको हैरानी होगी। घर के बगीचे में छोटे, हरे कच्चे-पके अमरूद को बेकार समझते हैं तो जरा इसके पोषक तत्वों के बारे में जान लें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल के मुताबिक दोनों फलों की न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अलग है। महंगे सेब को खाने से पहले एक बार अमरूद के पोषक तत्वों के बारे में जान लें...

सेब के मुकाबले अमरूद में कितना होता है न्यूट्रिशन

सेब और अमरूद के न्यूट्रिशन की तुलना की जाए तो रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं, जारें दोनों के न्यूट्रिशन

सेब और अमरूद में कितनी होती है कैलोरी

अगर आप डाइट पर हैं और वेट लॉस के लिए हेल्दी फूड के जरिए कैलोरी लेना चाहते हैं तो सेब खाते होंगे लेकिन सेब में जहां 52 कैलोरी होती है वहीं अमरूद में कैलोरी की मात्रा 68 होती है।

सेब और अमरूद खाने से कितना

प्रोटीन मिलेगा

प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स की बात करें तो जहां एक सेब खाने से मात्र 0.3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा वहीं एक अमरूद खाने से आपको 2.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है।

विटामिन सी की मात्रा चौंका देगी

हेल्दी स्किन और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सेब या अमरूद दोनों में क्या खाना फायदेमंद हो सकता है, इसका जवाब चौंका देगा क्योंकि जहां 1 सेब में 5 मिलीग्राम विटामिन सी होता है वहीं 1 अमरूद में 220 मिली ग्राम विटामिन सी होता है। इस दो सी गुना ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होने की वजह से ये फल आपकी बेहतर इम्यूनिटी के लिए सेब के कहीं ज्यादा फायदेमंद है।

फाइबर के लिए अमरूद होगा बेस्ट

वहीं अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सेब खाने से अच्छा है कि आप अमरूद को खाएं। एक सेब में जहां मात्र 2.4 ग्राम ही फाइबर मिलता है वहीं अमरूद में दोगुने से भी ज्यादा यानी 5.4 ग्राम फाइबर होता है।

पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होगी

सेब में पोटेशियम की मात्रा 107 मिलीग्राम होती है वहीं अमरूद में यही पोटेशियम 417 मिलीग्राम होता है। तो अगली बार महंगा समझकर सेब को बेस्ट ना समझें बल्कि इनके सस्ते ऑप्शन को खाने के बारे में जरूर सोचें।

ट्राई करें कटहल कोरमा की यहां बताई रेसिपी, खाने वाले चाटते रह जाएंगे उंगलियां

अगर आप कटहल खाते हैं तो एक बार यहां बताएं तरीके से कटहल कोरमा बनाकर ट्राई करें। अगर आप मसालेदार चीजें खाना पसंद करते हैं तो इस सब्जी का स्वाद आपको यकीनन पसंद आएगा...

• जालंधर ब्रीज. रेसिपी

कटहल एक ऐसी सब्जी है जिसे लोग या तो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें बनाना नहीं आता या फिर जैसा स्वाद वह इस सब्जी में चाहते हैं वह नहीं मिलता। ऐसे में आप कटहल कोरमा की यहां बताई रेसिपी एक बार ट्राई करें। ये स्वाद में जबरदस्त लगती है और तवा रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ अच्छी लगती है। यहां सीखिए मसालेदार कटहल कोरमा बनाने का तरीका।

कटहल कोरमा बनाने की सामग्री

- 500 ग्राम मीडियम टुकड़ों में कटा हुआ कच्चा कटहल
- 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल
- 4 बड़े प्याज (पतले कटे हुए)
- 300-400 ग्राम ताजा दही
- 2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
- 2 हरी मिर्च
- 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
- आधा छोटा चम्मच गुलाब जल
- आधा छोटा चम्मच केवड़ा जल
- 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
- आधा छोटा चम्मच हल्दी
- आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर
- आधा छोटा चम्मच गरम मसाला
- स्वादानुसार नमक
- जरूरत के अनुसार पानी
- गार्निशिंग के लिए ताजा धनिया
- गार्निशिंग के लिए अदरक के लच्छे

पीसने के लिए कोरमा मसाला

- 1 बड़ी इलायची

• जालंधर ब्रीज. हेल्थ केयर



- 3 हरी इलायची
- 2-3 टुकड़े जावित्री
- एक छोटा टुकड़ा जायफल
- आधा चक्र फूल
- 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी
- 8-10 काली मिर्च
- 3-4 लौंग
- 1 छोटा चम्मच जीरा
- आधा छोटा चम्मच सौंफ
- 1 बड़ा चम्मच सूखी गुलाब की पंखुड़ियां
- आधा तेजपत्ता

कटहल कोरमा बनाने की विधि

- कटहल को धोएं और फिर सूखने के बाद गर्म तेल में मीडियम आंच पर हल्का सूनहरा होने तक तलें। तेल से इसे निकालकर अलग रख दें।
- उसी पैन में कटे हुए प्याज को गहरा सूनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। फिर निकालकर ठंडा करें और हल्का सा क्रश कर लें।
- अब सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म करें, फिर आंच

धीमी कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें।

- इस तेल में फेंटा हुए दही और पिसे हुए मसाले डालें। अदरक-लहसुन, क्रश किए हुए कुरकुरे प्याज,कसूरी मेथी, गुलाब जल और केवड़ा डालें।
- अब धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि तेल और घी मसाले से अलग न हो जाएं।
- तला हुआ कटहल डालें और 3-4 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं।
- कोरमा मसाला और थोड़ा पानी डालें। अच्छी तरह मिलाएं और गाढ़ापन एडजस्ट करें।
- इसमें हरी मिर्च डालें और इसको ढक दें। अब धीमी आंच पर 15 मिनट तक पकाएं। धीरे-धीरे पकाने के लिए आप नीचे एक भारी तवा रख सकते हैं।
- आखिर में ऊपर से ताजा हरा धनिया और अदरक के लच्छे डालें और सर्व करें।

पंपकिन से लेकर अलसी के बीज जैसे 6 सीड्स को खाने का सही तरीका जान लें

Health



की मजबूती के लिए महिलाओं को तिल जरूर खाना चाहिए। तिल को जब भी खाना हो तो इसे तड़का लगाकर खाना अच्छा होता है। तभी इसके हेल्दी फैट्स और न्यूट्रिशन बाँटी को मिलते हैं।

अलीव सीड्स या हलीम के बीज

हलीम के बीज में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जिन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनके लिए ये बीज अमृत की तरह है। लेकिन इसके पूरे फायदे तभी मिलेंगे जब इसे सही तरीके से खाया जाएगा। हलीम के बीजों को हमेशा रातभर पानी में भिगोकर सुबह के समय खाना चाहिए।

हेल्दी रहने और शरीर को सही पोषण देने के लिए कई तरह के बीजों को खाया जाता है, जैसे पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, प्लैक्स सीड्स लेकिन इन सबको खाने का सही तरीका पता होना चाहिए...

सनफ्लावर सीड्स

वहीं सनफ्लावर सीड्स जिसमे विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अगर एक कप यानि 45 ग्राम के करीब सनफ्लावर सीड्स खाया जाए तो इसमें रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा विटामिन ई मिलता है और विटामिन ई स्किन-बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सनफ्लावर के इतने सारे फायदों के लिए खाना है आराम से कच्चा खा सकते हैं।

नोट : इस खबर में बताए गए सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। इसलिए किसी भी उपचार/दवा/डाइट को अमल करने से पहले डाक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

डिस्क्लेमर : इस लेख में किए गए दावे यूट्यूब वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।

स्टील फ्रेम का पुनर्निर्माण : शासन करने से लेकर सेवा तक, समयबद्ध सुधारों का सिलसिला

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

जब अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर वापस ब्रिटेन जाने लगे, तो वे एक मुहावरा अपने पीछे छोड़ गए : "स्टील फ्रेम"। इसे वे भारतीय सिविल सेवा कहते थे, जब प्रशासनिक ढांचा जिसके जरिए ब्रिटिश राज अपनी हुकूमत चलाता था। स्टील आसानी से नहीं झुकता, और यही वास्तविक बात थी। यह ढांचा एक साम्राज्य को स्थिर बनाए रखने के लिए बनाया गया था, न कि उन लोगों की बात सुनने के लिए जिन पर उसने शासन किया था। आजादी के बाद दशकों तक हमें वो फ्रेम विरासत में मिला। हमने उसे नया नाम दिया, उसे खादी का आवरण पहनाया और खुद को बताया कि अब यह हमारा अपना है। लेकिन नियंत्रण के लिए बनाया गया फ्रेम स्‍वोभाविक रूप से सेवा के लिए बनाया गया ढांचा नहीं है। और हमारे गणतंत्र के पहले कई दशकों तक, भारत अपने उपनिवेशक देश के ढांचे के अंदर ही बना रहा। एक ही फॉर्म को तीन प्रतियों में दाखिल करता रहा, उन्ही ऊंची कुर्सियों के सामने कतारों में खड़ा होता रहा और अपने भाग्य के फैसले के लिए किसी "साहब" की प्रतीक्षा करता रहा। मैंने अपने कामकाजी जीवन का अधिकांश समय इस ढांचे के अंदर बिताया है। पहले एक नागरिक के रूप में और एक

प्रोफेशनल के रूप में, फिर भारत सरकार में कामिक, लोक शिकायत और पेंशन का प्रभार सौंपे गए मंत्री के रूप में, जिस विभाग का काम ही स्टील फ्रेम की जांच करना और यह पृष्ठना है कि क्या फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या भारत ने अपनी नौकरशाही में सुधार किया है, तो मेरे उत्तर में न तो किसी संस्थान की रक्षा करने वाले व्यक्ति का ढाल बनना है, न ही किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा है जिन्हने इसे छोड़ दिया है। यह एक ऐसे व्यक्ति का उत्तर है, जिसने एक ऐसी प्रणाली के बारह वर्षों के शांत लेकिन दृढ़ पुनर्निर्माण को अंदर से देखा है, जिसे स्वतंत्रता के बाद से सार्थक रूप से नहीं छुआ गया था। अगर नरेंद्र मोदी, जो अपनी पथ-प्रदर्शक सोच के लिए जाने जाते हैं, भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार नहीं संभालते तो शायद अब भी अछूता रह गया होता।

विचार करें कि हमने कहाँ से शुरुआत की। 2014 में, केंद्र सरकार से एक नागरिक की शिकायत को अगर हल कर लिया गया, तो इसे करने में औसतन 157 दिन लगे। अगर शिकायत दर्ज कर रही ली गई, तो इसका मतलब देश भर में फैले मुश्किल से दस हजार शिकायत अधिकारियों के साथ एक प्रणाली की खोज करना था, जिनमें

से अधिकांश तक पहुंच नहीं थी और वे सभी किसी भी वास्तविक समय सीमा के प्रति कोई जवाबदेह नहीं थे। नौकरी के लिए सरकारी कार्यालय के बाहर कतार में खड़ा एक युवक, अपने पति की पेंशन फ़ाइल का पता लगा रही एक विधवा, यह जानने की कोशिश में लगा एक किसान कि उसके फसल बीमा दावे की फाइल किस मंत्रालय की रक्षा करने वाली मारी में से क्यों गायब हो गई, इन सवाके सामने एक ही स्थिति थी। उनका सामना नागरिकों को प्रतीक्षा कराने के लिए डिज़ाइन की गई एक सिस्टम से और ऐसे अधिकारियों से था, जिनका किसी भी परिणाम के प्रति कोई उत्तरदायित्वक नहीं था। यह केवल अक्षमता नहीं थी। यह उस प्रशासन का अंतिम जीवित अवशेष था जिसका निर्माण समाधान उपलब्धक कराने के बजाय डराने के लिए किया गया था।

आज के साथ इसकी तुलना राय का विषय नहीं है; यह संख्याओं में वर्णित है। शिकायत निपटान का समय 157 दिन घटकर 15 दिन रह गया है। आज का हमारा सिस्टमस नौ गुना अधिक सालाना लगभग

3 लाख से बढ़कर 27 लाख शिकायतों का निवारण करता है। इन शिकायतों का निवारण करने वाले अधिकारियों की संख्या दस गुना से अधिक बढ़कर एक लाख तक पहुंच गई है। इस वर्ष मार्च में ही, केंद्रीय सचिवालय ने लगातार पैतालीसवें महीने में एक लाख शिकायतों के निवारण के आंकड़े को पार कर लिया है। हमने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) का एक ऐसे प्लेहटफॉर्म में निर्माण किया है जो अब 22 भाषाओं में बोलता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक नागरिक की शिकायत को सही डेस्क पर ले जाता है। यहां तक कि एक दूरस्थ गांव में एक किसान की आवाज में, उसकी अपनी भाषा में, एक चैटबॉट के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। काफी जानबूझकर,

हमने इसका नाम समाधान दीदी अर्थात् "समाधान करने वाली बहन" रखा था। जिस ग्रामीण को अपने काम के लिए कभी जिला कार्यालय की यात्रा करने की आवश्यकता होती थी और उम्मीकद करनी होती थी कि उसका काम सरलता से हो जाए, वह अब



डॉ. जितेंद्र सिंह (लोक केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं)

अपनी पंचायत में एक सामान्य सेवा केंद्र से यह काम कर सकता है। हर महीने की बीस तारीख को सीएससी-सीपीजीआरएएमएस दिवस के रूप में निर्धारित किया जाता है ताकि यह वादा अंतिम मील तक पहुंच सके। लेकिन वह गहरा परिवर्तन, जिसे मैं स्टील फ्रेम का सच्चा सुधार मानता हूं, वह डिजिटल प्लंबिंग नहीं है। यह इस दर्शन में बदलाव है कि हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों का निर्माण कैसे करते हैं। 70 वर्षों तक, सरकार "नियम-आधारित" संस्कृति पर चलती रही: एक अधिकारी को इस बात से आंका जाता था कि क्या उसने सही प्रक्रिया का पालन किया था, न कि इस बात से कि उसने नागरिक की समस्या को हल किया है या नहीं। 2020 में, हमने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया, जो प्रशासनिक सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हमने इस कार्यक्रम को इसी "भूमिका-आधारित" संस्कृति में परिवर्तित करने के लिए लॉन्च किया था, जहां एक अधिकारी को इस आधार पर प्रशिक्षित और मूल्यांकन किया जाता है कि उसकी नौकरी वास्तव में उससे क्या मांग करती है, न कि औपनिवेशिक युग की नियम पुस्तिका में क्यान वर्णन किया गया है। आज एक ग्राम-स्तरीय क्लर्क से लेकर भारत सरकार के सचिव तक 1.65 करोड़

से अधिक सरकारी कर्मचारी, आईजीओटी कर्मयोगी नामक एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीखते हैं, जो अब हिंदी और सत्रह अन्य भारतीय भाषाओं में पांच हजार से अधिक पाठ्यक्रम संचालित करता है। पहली बार, हमने औपचारिक रूप से इस सीखने को एक अधिकारी की पदोन्नति के लिए आवश्यक वार्षिक मूल्यांकन अर्थात् निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट से जोड़ा है। अब निरंतर सीखना एक गुण नहीं रह गया, जिसका कोई अच्‍छाच अधिकारी अन्यास करता है, बल्कि इसे सीधे उसके करियर से जुड़ा हुआ एक मापदंड (मेट्रिक) बना दिया गया है। यह निष्पा दन जवाबदेही है, एक नए के रूप में नहीं बल्कि एक तंत्र के रूप में।

हमने अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण के तरीके से औपनिवेशिक अवशेषों को हटाने के लिए चुपचाप लेकिन लगातार काम किया है। 2016 के बाद से, निचले और मध्यम स्तर की सरकारी नौकरियों, ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी पदों के लिए साक्षात्कार, जिन पदों पर पारंपरिक रूप से एक साक्षात्कार का मतलब पक्षपात होता था और अक्सर रिश्तद दी जाती थी, को केंद्र सरकार के कार्यालयों में समाप्त कर दिया गया है। 24 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इसका अनुसरण किया है।

प्राकृतिक खेती - सतत कृषि और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

भारत ने पिछले दशक में कृषि क्षेत्र में तेज प्रगति की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, पिछले 5 सालों में विकास दर 4% से अधिक रही है। खाद्यान्न, बागवानी और तेलहन फसलों का बंपर उत्पादन हुआ है। यह किसानों द्वारा नई तकनीकों को अपनाने और सिंचाई वाले क्षेत्र का विस्तार, बेहतर जल उपयोग दक्षता और समय पर व पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्धता जैसी सरकार की ठोस नीतियों के समर्थन का परिणाम है। बागवानी फसलों की हिस्सेदारी भी काफी बढ़ रही है और इसकी विकास दर अपेक्षाकृत अधिक है।

हालाँकि, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और प्रमुख फसलों की उत्पादकता में स्थिरता आ रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) में धीरे-धीरे आई कमी के कारण एक ऐसा दुष्प्रक्र बन गया है, जिसमें किसान रासायनिक खादों की मात्रा तो लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादकता में बहुत मामूली बढ़ोतरी ही हो रही है।

सरकार को मुदा स्वास्थ्य और उर्वरक योजना के तहत 26 करोड़ मुदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण किया गया है। इससे प्राप्त डेटा के अखिल-इंडिया विश्लेषण से चिंताजनक बात सामने आई है कि मिट्टी में जैविक कार्बन (एसओसी) और अन्य जरूरी सूक्ष्म-पोषक तत्वों की भारी कमी है। स्वस्थ मिट्टी में एसओसी 1% से अधिक होना चाहिए, लेकिन यह औसतन 0.5% के आसपास है और कुछ क्षेत्रों में यह 0.3% तक के यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

कम मात्रा में एसओसी से मिट्टी की संध्रता कम हो जाती है, जिसका दोहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है: पानी का जमीन में रिसाव और जल धारण क्षमता, दोनों में कमी आती है। परिणामस्वरूप, वर्षा और सिंचाई का पानी बह जाता है, जो ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है और न तो यह जमीन के नीचे जाकर भूजल

स्तर बढ़ा पाता है और न ही पौधों की वृद्धि के लिए आसानी से उपलब्ध रहता है। कम एसओसी का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि ऐसे मिट्टी पर उगाए जाने वाले पौधों की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। समान उत्पादकता स्तर तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई खुराक उर्वरक उपयोग दक्षता को और कम कर देती है, जिससे मृदा-स्वास्थ्य का नुकसान होता है और देश रासायनिक उर्वरकों या

उनके घरेलू उत्पादन के कच्चे माल को आयात करने में अपनी कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करता है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के असंतुलित उपयोग ने उन लाभकारी सूक्ष्मजीवों और कीड़ों को भी कम कर दिया है, जो मिट्टी की संध्रता को बेहतर बनाने और गहरी मिट्टी से पोषक तत्वों को ऊपरी मिट्टी तक स्थानांतरित करने में मदद करते हैं, ताकि पौधे उन्हें अवशोषित कर सकें। एक अन्य चिंताजनक प्रभाव उपज की गुणवत्ता और सुरक्षा पर पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि रसायन खाने-पीने और पशु चारे की श्रृंखला में पहुंच जायेंगे और आखिरकार मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करेंगे। ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें फलों, सब्जियों, अनाज और अन्य वाणिज्यिक फसलों में कीटनाशकों का न्यूनतम अवशेष स्तर तथ सीमा को पार कर गया है, जिसके चलते निर्यात की खेपें रद्द होती हैं और वैश्विक बाजार में ब्रांड इंडिया की छवि पर बुरा पड़ता है।

हालाँकि ये चिंताएँ कुछ समय से व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन सरकार ने वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत कृषि के लिए पशुधन या गाय आधारित रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है, ताकि मिट्टी की सेहत खासकर एसओसी में सुधार हो सके, पौष्टिक तत्वों के अवशोषण की क्षमता बढ़ सके और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर देश की निर्भरता कम हो सके।

• जालंधर ब्रीज . चंडीगढ़

गैंगस्टर्स ते वार’ मुहिम के दौरान अंतर-राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता दर्ज करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ओवरसीज़ फ्यूजिवि्ट ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडीशन सेल (ओ.एफ.टी.ई.सी.) ने केंद्रीय एजेंसियों के तालमेल से दविंदर बंबोहा गिरोह के तीन वांछित कार्यकर्ताओं की सुरक्षित प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया है। यह जानकारी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहाँ दी।

प्रत्यर्पित किए गए आरोपियों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ जस बहिबल, निवासी फरीदकोट और अजय सिंह तथा पवनदीप सिंह, निवासी श्री गंगानगर, राजस्थान के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मलेशिया से भारत लाए गए तीनों

आरोपियों को पंजाब पुलिस ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया और बाद में आगे की जांच के लिए उन्हें पंजाब लाया गया।

डीजीपी ने कहा कि ये तीनों आरोपी मलेशिया स्थित दविंदर बंबोहा गिरोह के प्रमुख गुर्गों हैं और इनके पाकिस्तान की आईएसआई से भी संबंध हैं। उक्त तीनों आरोपी हत्या, जब्तन वसूली, विस्फोटक और लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट को योजना बनाने सहित कई मामलों में वांछित हैं।

अधिक विवरण साझा करते हुए, अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (एडीजीपी) काउंटर इंटेलिजेंस अमित प्रसाद ने कहा कि इन तीनों भगोड़ों का प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी एक निरंतर खुफिया-आधारित कार्रवाई का परिणाम

है, जो कई महीनों तक जारी रही, जिसके दौरान भगोड़ों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि पूर्ण समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप उन्हें मलेशिया में हिरासत में ले लिया गया और भारत भेज दिया गया। इस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) ओ.एफ. टी.ई.सी. आशीष चौधरी ने बताया कि आरोपी जसप्रीत उर्फ जस बहिबल जून 2019 में मलेशिया गया था, जहां वह एक भगोड़ गैंगस्टर के संपर्क में आया, उसी के माध्यम से वह दविंदर बंबोहा गिरोह में शामिल हुआ और धीरे-धीरे गिरोह के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के रूप में उभरा। उन्होंने कहा कि आरोपी को 2025 में यादविंदर सिंह और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पूर्व आगू जीवनजोत सिंह चाहल उर्फ जुगनू के ड्राइवर की हत्या के



सीबीसी चंडीगढ़ ने साइबर जागरुकता पर कार्यशाला की

• जालंधर ब्रीज . चंडीगढ़

केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा “साइबर जागरूकता एवं सोशल मीडिया का प्रभाव” विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रेस सूचना ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न फील्ड कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रीतम सिंह, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में प्रभावी जनसंचार के लिए साइबर जागरूकता और सोशल मीडिया का जिम्मेदार उपयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के साथ कार्य किया जाता है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को साइबर खतरों, फिशिंग, सदिग्ध लिंक, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा भ्रामक सूचनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

प्रीतम सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया जनसंचार और नागरिकों तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाना का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले उसकी सत्यता और स्रोत की पुष्टि अवश्य करें। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय आधिकारिक जानकारी, व्यक्तिगत डेटा एवं संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। सपना, उप



निदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, चंडीगढ़ ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के दौर में प्रत्येक सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए डिजिटल और साइबर जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं, नीतियों और जनहितकारी सूचनाओं को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ गलत सूचना और भ्रामक सामग्री के प्रसार की चुनौती भी मौजूद है। उन्होंने प्रतिभागियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने, सदिग्ध लिंक एवं अटेंचमेंट से सावधान रहने तथा किसी भी असामान्य ऑनलाइन गतिविधि के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। कार्यशाला में डॉ. सुमेश सिंह, प्रोफेसर, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने “सोशल मीडिया का प्रभाव” विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया के बदलते स्वरूप और समाज, संचार तथा जनमत पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचनाओं के आदान-प्रदान और लोगों से जुड़ने की प्रक्रिया को तेज एवं आसान बनाया है।

इसके माध्यम से जागरूकता, जनभागीदारी और सूचना के व्यापक प्रसार को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ गलत सूचना, अपुष्ट सामग्री तथा सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से सोशल मीडिया का संतुलित, विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग करने का आग्रह किया। गुरचरण सिंह, फैकल्टी सदस्य, केंद्रीय अन्वेषण प्रशिक्षण संस्थान (CDIT), चंडीगढ़ ने “साइबर जागरूकता” विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों और उनसे बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सदिग्ध ई-मेल, संदेश, लिंक और ऑनलाइन अनुरोधों पर सावधानी बरतने तथा महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मजबूत पासवर्ड, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार और साइबर घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग को साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा से संबंधित व्यवहारिक सावधानियों, डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग तथा सोशल मीडिया पर जिम्मेदार आचरण के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के प्रभाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यशाला का उद्देश्य कार्यालयीन कार्यों में डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साइबर खतरों एवं सोशल मीडिया से संबंधित चुनौतियों के प्रति अधिक जागरूक बनाना था।

एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सुधारों का अगला चरण

• जालंधर ब्रीज . नई दिल्ली

1. संसद के दोनों सदन में हाल ही में पारित किया गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक, 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। एमएसएमई राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, एमएसएमई क्षेत्र ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' पर 9 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं, जो 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एमएसएमई हमारी आर्थिकी में 31% तथा निर्यात में 50% योगदान देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकासित भारत के संकल्प को साकार करने में एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख भागीदारी है। एमएसएमई भारत के विकास के सूत्रधार हैं। हाल के वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो "उद्यम" पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या से ही स्पष्ट दिखती है, जो 1 अप्रैल 2023 को 1 करोड़ 65 लाख से बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गए हैं।

2. वर्ष 2020 में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण को, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के अंतर को समाप्त करके, अधिक व्यापक और समावेशी बनाया गया था। इसके तहत टर्नओवर और निवेश दोनों पर आधारित एक समग्र मानदंड विकसित किया गया।

इसके पश्चात वर्ष 2025 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निवेश सीमा ढाई गुना बढ़ाकर क्रमशः ढाई करोड़, पच्चीस करोड़ और एक सौ पच्चीस करोड़ की गई है एवं टर्नओवर को दो गुना बढ़ाकर क्रमशः दस करोड़, सौ करोड़ और पांच सौ करोड़ किया गया, जिसने इन उद्यमों को पूंजी निवेश बढ़ाने, विज्ञान और तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

3. वित्त की उपलब्धता एमएसएमई क्षेत्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है और इसके उल्लेखनीय परिणाम दिख रहे हैं। एमएसएमई को प्रदान किया गया बकाया ऋण, वर्ष 2014–15 में 10 लाख करोड़ रुपये था, जो कि अब बढ़कर 38 लाख 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज' (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लिए जाने वाले ऋण पर गारंटी उपलब्ध कराता है। इसके ज़रिए वर्ष 2000 से 2022 के बीच, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दी गई क्रेडिट गारंटी 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये थी, जो पिछले चार वर्षों में अर्थात् 2022–23 से 2025–26 तक बढ़कर 10 लाख 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत,

वित्त वर्ष 2014–15 से अब तक लगभग 8 लाख 34 हजार सूक्ष्म उद्यमों को 24 हजार 903 करोड़ रुपये की मार्गिन मनी सब्सिडी दी गई है, जिससे अनुमानित 75 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

4. एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सालाना 25% खरीद करना अनिवार्य है; इसमें महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 3% और एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4% खरीद शामिल है। विगत वर्षों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद में लगातार वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सार्वजनिक खरीद का मूल्य 40,717 करोड़ रुपये था जो कि वित्तीय-वर्ष 2025–26 में बढ़कर 1,15,801 करोड़ रुपये हो गया है, जो सीपीएसई द्वारा खरीद के लिए लक्षित 25 प्रतिशत की तुलना में 49 प्रतिशत से अधिक है। इसमें एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से 3,984 करोड़



शोभा करंदलाजे (लैलिका केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा बंधु एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।)

रुपये की खरीद हुई और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली उद्यमों से 9,059 करोड़ रुपये की खरीद हुई है।

5. एमएसएमई को उनका भुगतान समय पर दिलाने हेतु मंत्रालय ने कई सार्थक प्रयास किए हैं, ट्रेड्स इनमें से एक है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है,

जिसे भारत में एमएसएमई की लिक्विडिटी (नकदी) संबंधी चुनौतियों तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने एमएसएमई क्षेत्र को मार्च 2026 तक 8,71,000 करोड़ रुपये की इनवॉइस डिसकाउंटिंग के माध्यम से समय पर भुगतान दिलवाया है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जुड़े एमएसएमई की संख्या अप्रैल 2022 में 34,430 थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 2,55,000 से अधिक हो गई है। वहीं, एमएसएमई की इनवॉइस डिसकाउंटिंग की राशि वर्ष 2021–22 में 40,000 करोड़ रुपये से बढ़कर, वित्त वर्ष 2025–26 में 3,47,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। ट्रेड्स पर इनवॉइस डिसकाउंटिंग का बढ़ता चलन, भारत सरकार के एमएसएमई के समग्रबद्ध भुगतान के प्रति संकल्प को

दर्शाता है।

6. इसी दिशा में विलंबित भुगतान और उससे जुड़े विवादों के निपटारे हेतु पूरे देश में 161 सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) स्थापित किए गए हैं। संशोधन में राज्यों को एमएसईएफसी की संरचना तय करने के लिए सक्षम बनाने के लिये प्रावधान लाए गए हैं जिससे आवश्यकतानुसार एमएसईएफसी का गठन किया जा सके। संबंधित पक्षों में समझौते के साथ विवाद सामाधान के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। यह संशोधन विधेयक ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को सक्षम एवं सशक्त बनाता है, ताकि संबंधित पक्षों द्वारा अपने विवादों का समयबद्ध और फिकायती तरीके से हल सुनिश्चित किया जा सके।

7. एमएसएमई मंत्रालय महिला उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के अनेक योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। आज उद्यम पोर्टल पर 39% से अधिक एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व में हैं, यानि 3.38 करोड़ के लगभग एमएसएमई महिला स्वामित्व में हैं और जिनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, महिलाओं के लिए 90% तक गारंटी कवरेज है और सालाना गारंटी फीस में 10% तक की छूट प्रदान की जाती है। खरीद और

विपणन सहायता योजना के तहत ट्रेड फेयर में महिला उद्यमियों की भागीदारी पर 100% सब्सिडी दी जाती है, जबकि दूसरे उद्यमियों के लिए एव ह 80% है। पीएमईजीपी में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 35 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 25 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति का विकास, मंत्रालय की प्राथमिकता है। आज उद्यम पर 1.24 करोड़ से अधिक एमएसएमई, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति का विकास, मंत्रालय की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति बंधु योजना, एमएसएमई मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2016 में माननीय प्रधानमंत्री ने शुरु किया था। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की क्षमता बढ़ाना और उनके बीच "उद्यमिता संस्कृति" को बढ़ावा देना है।

8. मंत्रालय की इन निरंतर पहलों और प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक, 2026 पास किया गया है। इसका उद्देश्य है—एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) और नियमों का अनुपालन करने को बढ़ावा देना।

'ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट' अब केवल एक क्लिक की दूरी पर : हरपाल सिंह चीमा

कहा- ऑनलाइन सुविधा वाहन मालिकों और कर्मशियल ऑपरेटरों के लिए 24 घंटे निर्बाध सेवाएं और व्यापारिक सरलता सुनिश्चित करेगी

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को यहां घोषणा की कि अब ‘ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट’ (एआईटीपी) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल (परिवहन) के माध्यम से आवेदकों को सीधे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।

यहां जारी एक प्रेस बयान के माध्यम से यह जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, "पहले टूरिस्ट वाहन संचालकों को राज्य परिवहन प्राधिकरण, मोहाली (पीबी01) के कार्यालय से जाकर स्वयं मुद्रित परमिट लेने पड़ते थे। इस डिजिटल सुविधा के शुभारंभ के साथ, आवेदक अब अपने घर या कार्यालय में बैठे ही आसानी से आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की



आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो गई है।"

राज्य सरकार की नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "भगवंत मान सरकार जनसेवाओं को सुगम, पारदर्शी और पूर्णतः परेशानी-मुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जारी करने की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन करके, हमने कार्यालयी लालफीताशाही को समाप्त किया है और सरकार तथा नागरिकों के बीच की दूरी को मिटाया है। आवेदकों को अब मोहाली कार्यालय के चक्कर काटने या लंबी कतारों में खड़े होने की

‘वन थाउज़ेंड वर्ड्स’ ने तस्वीरों के जरिए सुनाई हजारों कहानियां

दो दिवसीय 10वीं वार्षिक फोटो प्रदर्शनी अमित यादें छोड़ते हुए संपन्न, 42 तस्वीरों ने मानव जीवन, प्रकृति और भावनाओं के विभिन्न रंग किए प्रस्तुत



• **जालंधर ब्रीज.** लुधियाना

लुधियाना फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से रख बाग के निकट लक्ष्मी लेडीज़ क्लब में आयोजित दो दिवसीय 10वीं वार्षिक ‘वन थाउज़ेंड वर्ड्स’ फोटो प्रदर्शनी गुरुवार को अमित यादें छोड़ते हुए संपन्न हो गई। यह प्रदर्शनी केवल तस्वीरें देखने का अवसर ही नहीं रही, बल्कि मानव जीवन, प्रकृति, भावनाओं और समाज के विभिन्न रंगों को करीब से समझने का एक संवेदनशील साझा मंच भी बनी। प्रदर्शनी में लगाई गई 42 तस्वीरों ने बिना कुछ कहे दर्शकों के साथ संवाद स्थापित किया और अपने भीतर अनेक कहानियां समेटे हुए दिखाई दीं। प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही दर्शकों को यह एहसास हो रहा था कि वे किसी सामान्य फोटो प्रदर्शनी में नहीं, बल्कि एक ऐसे कलात्मक संसार में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर तस्वीर की अपनी अलग कहानी और अपना विशेष अहसास था। किसी तस्वीर में जीवन की खुशी और उत्साह नजर आया तो किसी में खामोशी

के दर्द और संवेदनाओं की झलक दिखाई दी। कहीं प्रकृति की खूबसूरती ने दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं कई तस्वीरों ने समाज की वास्तविकता को सामने रखते हुए लोगों को कुछ पल रुककर सोचने के लिए मजबूर कर दिया।

प्रदर्शनी देखने के लिए विद्यार्थियों से लेकर युवाओं, बच्चों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, पत्रकारों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। दर्शकों ने सभी 42 तस्वीरों को बड़ी गहराई और उत्सुकता के साथ देखा। हर तस्वीर के सामने खड़े होकर लोग उसके विषय, भावना और उसके पीछे छिपी कहानी को अपने-अपने नजरिए से महसूस करते दिखाई दिए। समापन समारोह के दौरान कोठी मेला से संचित अरोड़ा, सत्री गोयल, ली फोर्ड के प्रबंधकीय बोर्ड के सदस्य, प्रमोद बहल, अंसल एस्टेट से एस.एस. खुराना, अशंदीप समर और सुरेंद्र डल्ला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से पहुंचे।

पंजाब अब ‘उड़ता पंजाब’ से ‘पढ़ता पंजाब’ बन चुका है : हरजोत बैंस

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर भाजपा द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार का पर्दाफाश करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब को बदनाम करने और लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 के सात वर्ष पुराने वीडियो को नया बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने वीडियो में दिखाए गए फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव जल्ला स्थित सरकारी स्कूल का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और वहां की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल की वर्तमान स्थिति वीडियो में दिखाई गई तस्वीर से पूरी तरह अलग है। स्कूल में अब स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल, साफ-सुथरे और चालू शौचालय, सैनिटरी पैड इन्सिनेरेटर, स्वच्छ पेयजल तथा वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है। भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों और उपलब्धियों

का उल्लेख करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीसीआई) 2.0 तथा कक्षा-कक्षा में सीखने के परिणामों के मामले में देशभर में अग्रणी रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने यूजी-नीट 2026 परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सर्वेक्षण में पंजाब के 23वें स्थान वाले जिले पटियाला ने भाजपा शासित हरियाणा के शीर्ष स्थान वाले जिले गुरुग्राम से भी अधिक अंक हासिल किए।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था, जिसे बाद में सांसद हरभजन सिंह ने भी आगे पोस्ट किया।

आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सब कुछ उनकी उंगलियों पर उपलब्ध है।"

परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि यह पहल परिवहन सेवाओं के डिजिटल विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बहुमूल्य समय की बचत होगी और अनावश्यक प्रशासनिक विलंब पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा, "हमारे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए समय अत्यंत मूल्यवान है। यह डिजिटल सुधार न केवल पलक झपकते ही सेवाएं उपलब्ध कराता है, बल्कि दक्षता और जवाबदेही का एक नया मानक भी स्थापित करता है। दस्तावेजी प्रक्रिया को आरंभ से अंत तक सरल बनाकर, हम राज्य के परिवहन क्षेत्र में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में सरलता) का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।"

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वाहन मालिक और वाणिज्यिक आपरेटर राष्ट्रीय परिवहन पोर्टल के माध्यम से सीधे अपने स्वीकृत ए.आई.टी.पी. दस्तावेजों को देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे 24 घंटे सुविधा और निर्बाध व्यावसायिक गतिविधियां सुनिश्चित होंगी।

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पेंशनरों को पौधे वितरित

सीसीए पंजाब द्वारा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया



• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यालय नियंत्रक, संचार लेखा (सीसीए), पंजाब टेलीकॉम सर्किल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनरों की बहुमूल्य सेवाओं और योगदान के सम्मान में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 2026 मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन यू.टी. गेस्ट हाउस, चंडीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजेंद्र एन. टंडन, नियंत्रक संचार लेखा (सीसीए), पंजाब द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों एवं प्रतिभागियों के स्वागत के साथ हुआ, जिसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के लाभ एवं कल्याण हेतु विभिन्न जागरूकता एवं कल्याणकारी सत्र आयोजित किए गए। वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सेवाओं के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग तथा साइबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूक करने के लिए डिजिटल एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। सिटी हॉस्पिटल की डायटीशियन सुश्री

सिमरन द्वारा “वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वस्थ जीवनशैली” विषय पर स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता दी गई। सत्र में संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा तनाव प्रबंधन सहित स्वस्थ जीवनशैली के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी गई। पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र एवं पेंशन संबंधी सेवाओं से परिचित करने के लिए जीवन प्रमाण एवं SAMPANN पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा ने वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनरों के लिए निरंतर सहयोग एवं कल्याणकारी उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं नियंत्रक संचार लेखा, पंजाब, विजेंद्र एन. टंडन ने अपने मुख्य संबोधन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुलभ, उत्तमदायी एवं पेंशनर-अनुकूल सेवाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा समाज में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव एवं बहुमूल्य योगदान को रेखांकित किया।

पीआईबी, जालंधर ने अमृतसर में ‘वार्तालाप’ मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) चंडीगढ़ की जालंधर शाखा द्वारा ‘वार्तालाप’ मीडिया कार्यशाला का आयोजन अमृतसर में किया गया, जिसमें विशेष रूप से अमृतसर के पत्रकार शामिल हुए। इस मीडिया कार्यशाला में “केंद्र सरकार की योजनाओं की जनकल्याण में भूमिका” विषय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के साथ चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान ‘अमृतसर में नेशनल हाईवे बुनियादी ढांचे के विस्तार में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका’ विषय पर चर्चा करते हुए जसप्रीत, मैनेजर टेक्नोलॉजी (एनएचएआई), अमृतसर ने बताया कि एनएचएआई पीआईयू अमृतसर के सड़क बुनियादी ढांचे से संबंधित करीब 595 किलोमीटर के करीब 5,668 करोड़ रुपये



की लागत के 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 9 प्रोजेक्टों का कार्य पूरा हो चुका है। जसप्रीत ने बताया कि नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सहायता के लिए नेशनल हाईवे हेल्पलाइन 1033 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अमृतसर से डॉ. अमरदीप सिंह, जिला मास शिक्षा एवं सूचना अधिकारी ने “नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) की योजनाओं की जनकल्याण में भूमिका” विषय पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यदि देश के लोग

स्वस्थ होंगे तो देश की प्रगति में वे अपना पूरा योगदान दे सकेंगे। डॉ. अमरदीप ने कहा कि इसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की कई योजनाएं हैं। उन्होंने बताया कि जिला अमृतसर में 178 हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक हैं, जो गांवों में सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना और टीकाकरण सहित अनेक कार्यक्रम लोगों को अच्छी

महिला अधिकारियों को अग्रणी भूमिकाएं निभाने के लिए आगे आने की जरूरत : स्पेशल डीजीपी



पंजाब पुलिस का वर्ष भर चलने वाला लिंग

संवेदनशीलता एवं मेनस्ट्रीमिंग प्रशिक्षण

परियोजना एमआरएसपीपीए फिल्लौर में हुआ

संपन्न, 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रयास से कार्य में आती है उत्कृष्टता : मनराज ग्रेवाल शर्मा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/जालंधर

पंजाब पुलिस, आरसीटी एनजीओ– जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) एवं हार्टेक फाउंडेशन के सहयोग से, ‘लिंग संवेदनशीलता एवं पंजाब पुलिस में महिलाओं का मेनस्ट्रीमिंग’ विषय पर आधारित वर्ष भर चलने वाली प्रशिक्षण पहल आज 134 वर्ष पुरानी महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी (एमआरएसपीपीए), फिल्लौर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आज, तीसरे चरण का अंतिम दिन गुप्त टी। सी–केवल महिलाओं के लिए समूह पर केंद्रित रहा, जिसमें प्रदेश भर में महिला हेल्पडेस्कों पर तैनात पंजाब पुलिस महिला मित्र शामिल हुईं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची, इंडियन एक्सप्रेस की रजिडेंट/राष्ट्रीय संपादक (उत्तरी) मनराज ग्रेवाल शर्मा ने प्रतिभागी महिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि



कैसे उन्होंने इस पुरुष-प्रधान क्षेत्र में चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए पत्रकारिता में सम्मानजनक स्थान हासिल किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शिखर तक पहुंचने के लिए बिना किसी समझौते के पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि हमेशा '5% अतिरिक्त प्रयास' हमें दूसरों से अलग एवं आगे कर देता है। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों से अपेक्षा रखी, अपनी व्यावसायिक महत्ता बनाने और कार्यस्थल पर लिंग आधारित या अनुचित टिप्पणियों के विरुद्ध डटकर बोलने की अपील की।

इस अवसर पर बोलते हुए स्पेशल डीजीपी कप्तानिटी अफेयर्स डिवीजन (सी.ए.डी.) गुरप्रीत कौर दिओ ने कहा कि पंजाब पुलिस की 80,000 कर्मचारियों की मजबूत संख्या में 11% महिला कर्मियों को गौरव एवं समानता के साथ मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ऐसी प्रशिक्षण पहल अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने महिलाओं से प्रशासनिक डेस्कॉ के आगे बढ़ने, चुनौतीपूर्ण फील्ड असाइनमेंट चुनने और स्टेशन हाउस अधिकारी (एस.एच.ओ.) के रूप में पोस्टिंग सहित फ्रंटलाइन नेतृत्व भूमिकाओं के लिए सक्रिय रूप से आगे आने की अपील की।

आधार ऐप ने 5 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार किया

60 लाख से अधिक लोगों ने अपने मोबाइल नंबर और 15 लाख से अधिक लोगों ने अपने पते अपडेट किए

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

आधार ऐप ने 5 करोड़ डाउनलोड का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है, जो निवासियों के बीच सुविधाजनक और डिजिटल आधार सेवाओं के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। यह उपलब्धि निवासियों और यूआईडीईआई के बीच एक डिजिटल इंटरफ़ेस के रूप में आधार ऐप की भूमिका के महत्वपूर्ण विस्तार को चिह्नित करती है, जिससे आधार नंबर धारक अमरटीफोन से मोबाइल नंबर अपडेट, पता अपडेट, ईमेल अपडेट, बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक और ई-आधार डाउनलोड सहित कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। लॉन्च होने के बाद से ही इस ऐप का उपयोग लगातार और मजबूत तरीके से हो रहा है। आधार ऐप का उपयोग

करके 60 लाख से अधिक लोगों ने अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया, वहीं 15 लाख से अधिक लोगों ने पते और 23 लाख से अधिक लोगों ने ईमेल अपडेट किए। इन सेवाओं को अपनाने में हो रही वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि निवासी आधार केंद्र जाने की आवश्यकता के बिना, डिजिटल रूप से आधार से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। आधार ऐप को "दिखाएं, साझा करें और सत्यापित करें" के सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन किया गया है, जो आधार नंबर धारकों को उनकी आधार जानकारी के उपयोग पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है, साथ ही सुविधाजनक पहचान सत्यापन को सक्षम बनाता है।

आधार ऐप की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ, यूआईडीईआई सुरक्षित और सुविधाजनक ऑफलाइन सत्यापन के लिए इकोसिस्टम का विस्तार करना जारी रखे हुए है। जनवरी में इसकी शुरुआत के बाद से, यूआईडीईआई ने 200 से अधिक संस्थाओं

को ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाओं (ओवीएसएस) के रूप में शामिल किया है।

यह उपलब्धि आधार ऑफलाइन तंत्र के माध्यम से सुरक्षित, सहमत-आधारित और कामाज रहित सत्यापन को सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है – जो सेवा प्रदाताओं और लोगों दोनों को समान रूप से सशक्त बनाती है। इन ओवीएसई भागीदारों का जुड़ना आधार-आधारित, गोपनीयता-प्रथम डिजिटल सत्यापन ढांचों में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है जो उपयोगकर्ता नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए सेवाओं तथा आसान पहुंच सुनिश्चित करता है।

आधार ऑफलाइन सत्यापन विधियों जैसे कि क्यूआर कोड-आधारित सत्यापन और सुरक्षित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों का लाभ उठाकर, ये संस्थाएं अब यूआईडीईआई के केंद्रीय डेटाबेस से वास्तविक समय कनेक्टिविटी की आवश्यकता के बिना पहचान संबंधी जानकारी को सत्यापित करने में सक्षम होंगी।

दिलीप ट्रॉफी का फाइनल अब चेन्नई में

बीसीसीआई ने दर्शकों की सुविधा के लिए बदला मैदान

स्पोर्ट्स डेस्क. दलीप ट्रॉफी 2026–27 का अगले महीने होने वाला फाइनल बेंगलुरु के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ से हटाकर अब

पूर्वोत्तर क्षेत्र से जबकि उत्तरी क्षेत्र की भिड़ंत पश्चिम क्षेत्र से होगी। 2026–27 सत्र में दलीप ट्रॉफी में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस बार ट्रान्smेंट अपने पारंपरिक क्षेत्रीय प्रारूप में लौट आया है।

इसमें मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र की टीमें शामिल हैं। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि सीओई में दर्शकों की संख्या को लेकर कुछ सीमाएं हैं इसलिए फाइनल को चेन्नई स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा, “‘दलीप ट्रॉफी हमारे

लेकर कुछ सीमाएं हैं इसलिए फाइनल को चेन्नई स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा, “‘दलीप ट्रॉफी हमारे

घरेलू कैलेंडर का महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है।

इसमें हमेशा उच्च स्तर का क्रिकेट देखने को मिलता है और हम चाहते हैं कि प्रशंसकों को फाइनल मुकाबला स्टेडियम में देखने का मौका मिले। ” सैकिया ने कहा, “सीओई में दर्शकों की मौजूदगी को लेकर कुछ प्रतिबंध हैं। इसलिए हमें लगा कि फाइनल को ऐसे मैदान पर कराया जाना उचित होगा, जहां प्रशंसक आकर इस मुकाबले का हिस्सा बन सकें।

उन्होंने बताया कि ट्रान्smेंट का प्रसारण भी बढ़ाया गया है। दलीप ट्रॉफी के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी जबकि एक क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल का टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।



प्रमुख कंपनियों को पंजाब की क्षमताओं और विशेषताओं से अवगत कराया।

यह निवेश संपर्क कार्यक्रम मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उस मजबूत रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख व्यापारिक एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों में कॉरपोरेट निर्णयकर्ताओं,

जीसीसी प्रमुखों तथा इकोसिस्टम से जुड़े भागीदारों के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर पंजाब, विशेषकर मोहाली को वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। 19 और 20 अगस्त को आयोजित दो दिवसीय दौरे के दौरान अमन अरोड़ा ने पंजाब के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ज़िनोव कॉन्प्लुएंस् 2026 के सहयोग से प्रमुख जीसीसी कंपनियों के साथ उच्चस्तरीय सीएक्सओ गोलमेज बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा, विश्व की विभिन्न प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा पंजाब की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए इकोसिस्टम भागीदारों के साथ संभावित सहयोगी की रूपरेखा तैयार की गई।